

ation level not only in post offices but in other agencies also local languages have to be encouraged and given priority for the convenience of the public. This is not being done and I do not know whether it is deliberate or not deliberate. Nevertheless, it is causing considerable inconvenience, difficulty to these people. May I, therefore, ask the Minister concerned to look into this matter immediately? He is already aware of this situation. He must look into this matter immediately and see that the forms in Kannada are made available in all the post offices.

SHRI R. MOHANRANGAM (Tamil Nadu): I also associate myself with Mr. Gurupadaswamy with regard to this particular issue. Also I have to state that I have seen a statement in Madras Hindu today wherein it is stated that the persons who go to foreign countries as foreign delegates hereafter have been instructed to converse only in Hindi and not in English or any other language. It appears that this memorandum has been sent by the Home Department to all the Central Government departments that they have to converse only in Hindi and not in any other language. Is it justifiable?

REFERENCE TO THE DEMAND FOR INCLUSION OF CHRISTIANS IN SCHEDULED CASTE AND SCHEDULED TRIBE LISTS

SHRI VALAMPURI JOHN (Tamil Nadu): Sir, I would like to draw the attention of the Government to the stark reality that the Christians of Scheduled Castes origin who are socially, educationally and economically backward have been condemned to the same social segregation as their Hindu counterparts who have been carrying the stigma of untouchability from time immemorial. They are discriminated against only because they do not profess Hindu or Sikh religion.

It is an admitted fact that they are denied of Central Government concessions and assistance on the

basis if Para III of the Constitution (Scheduled Caste Order) 1950, later amended by Parliament in 1956 which reads:

"Notwithstanding anything contained in Para II no person who professes a religion different from the Hindu or Sikh religion shall be deemed a member of the Scheduled Caste."

No sensible person would deny that the Christians of Scheduled Castes origin still continue to suffer from the stigma of untouchability both from the Hindu society and within the Christian community. There are numerous instances wherein the Hindu counterparts of Scheduled Castes origin themselves treat Christians of the same origin as untouchables and scheduled conglomerations. Change of religion has not placed even a single convert of scheduled castes in a highly elevated position of advantages. On the other hand, whether he is a Christian or a Hindu if he is of Scheduled Caste origin he is consigned to a beastly life of primitive darkness. They still continue to do menial jobs considered to be impure by caste Hindus and Christians alike. The recent Supreme Court judgement while appreciating the hardships that the Christians of scheduled castes origin undergo, has expressed its inability to do justice to them in the absence of unassailable evidence. Recently, the State Welfare Ministers in their meeting at New Delhi have recommended to the Central Government to revise the list of Scheduled Castes. Therefore, I would like to appeal to the Government that they may consider positively the demand of Christians of Scheduled Caste origin from the inauguration of the Constitution to include them in the constitutional list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I would like to point out that it is again a clear case of discrimination that Christians of certain communities in places like Kanvakumari district and Senkottah Taluk of Tamil Nadu are treated scheduled castes

[Shri Valampuri John]

and in other places are treated backward classes. This discrimination directly attracts article 14 of the Constitution in all its dimensions. Therefore, I would like to request the Government to consider the inclusion of Christians of scheduled castes origin in the constitutional list of scheduled castes when the revision takes place since the revision of the list is a constitutional obligation.

REFERENCE TO THE THREAT TO INTERNAL SECURITY OF THE COUNTRY DUE TO WIDESPREAD INFILTRATION FROM BANGLA- DESH AND PAKISTAN

श्री कैलाश पति मिश्र (बिहार) : उप-सभापति महोदय, जिस विषय पर स्पेशल मेशन है, उस पर काल अटेंशन के लिए कई माननीय सदस्यों ने लिखकर दिया था लेकिन समयान्तर के कारण वह स्वीकृत नहीं हुआ। भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर बहुत ही उदासीन दिखाई दे रही है।

श्रीमान, बिहार से सटे हुए बंगला देश से, पश्चिम बंगाल की तरफ लग हुए बंगाल देश से निरंतर घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं और बिहार प्रदेश के कई जिलों की आबादी का कंपोजिशन बदलता जा रहा है। वे देश के दूसरे भागों में फैलते जा रहे हैं। यहां तक कि खालिस्तान की तय्यकथित घोषणा के बाद स्वर्ण मन्दिर में जो तीन सौ लोग पकड़े गए, समाचार-पत्रों में छपा है कि उनमें से 25 बंगला देश के घुसपैठिए हैं। महोदय, यह विवाद का विषय नहीं है, मैं कुछ कंक्रीट उदाहरण देना चाहता हूं।

महोदय बिहार के साहबगंज जिले में जहां रेलवे लाइन बीच में है, वहां पर पुलिस ने नहीं, सरकार ने नहीं बल्कि नागरिकों ने अपना सतर्कता के कारण अनेक लोगों को पकड़ा 25-10-84 को बड़हरवा में 31 घुसपैठिए पकड़े गए। 30-10-84 को साहबगंज में 31 घुसपैठिए पकड़े गए। 21-1-86 को साहबगंज में 32 घुसपैठिए पकड़े गए। 16-2-86 को बड़हरवा में 53 घुसपैठिए पकड़े गए। 18-2-86 को 23 पकड़े गए। 4-3-86

को साहबगंज में 95 घुसपैठिए पकड़े गए इस प्रकार कुल मिलाकर 265 बंगला देश के घुसपैठिए पकड़े गए हैं जो कि फोरन एक्ट में जेल में बंद पड़े हुए हैं। सरकार क्या कर रहा है ? छानबीन करने के बाद पता लगाया तो जिला समाहर्ता व पुलिस सुपरटेंडेंट के पास जाकर मैंने पूछा कि देश पर इतना बड़ा खतरा पैदा हो रहा है आप क्या कर रहे हैं तो आश्चर्य लगा कि डिप्टी सुपरटेंडेंट के पास कोई जानकारी तक नहीं है। पुलिस सुपरटेंडेंट ने कहा कि हमारे पास इतना पुलिस बल ही नहीं है, गुप्तचर बल नहीं है जिसके आधार पर हम इस समस्या का समाधान कर सकें।

महोदय, और छानबीन करने के बाद पता लगा कि बंगला देश, पश्चिमी बंगाल और बिहार के बीच में गंगा आगे जाकर दो नदियों पदमा व भार्गवती में बंट जाती है उनके बीच में बड़ा रेत की जगह दिखाई देती है, जिसके दोनों ओर ब्रोकर हैं वे लोग घुसपैठियों को 5-7 दिन की ट्रेनिंग देकर उनको हर जगह भेजते हैं। उनको रेलवे स्टेशनों के नाम रटाते हैं और 25, 30, 100 आदमी एक साथ ट्रेन में बैठकर सब का टिकट लेकर एक ब्रोकर साथ वाले डिब्बे में बैठ जाता है। कोई गजानक पकड़ में आ गए तो वह गायब हो जाता है। जी० आर० पी० वाले वहाँ से गायब हो जाते हैं। वे अपने सिर बला लेना नहीं चाहते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि सी० आर० पी० वाले इन दलालों से पैसे खा रहे हैं। दूसरी ओर पूर्णिया जिला, कटिहार के पास तो सीमा 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर से लगी हुई है और घड़ल्ले से घुसपैठियों का निर्बाध प्रवाह हो रहा है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि वहाँ की स्थिति खतरनाक है। मवेशी, गाय, बैल आदि एक एक सप्ताह के अंदर 20 हजार के करीब बंगला देश जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। परिणाम यह हो रहा है कि सीमा पर किसानों के पास खेती करने के लिए बैल उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, इतने मंहंगे होते जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह समस्या विकट होती जा रही है। याद रखिए, पहले आसाम की समस्या भी समझ में नहीं आती थी लेकिन जब आसाम चलने लगा तो आप जानें और आज असम